PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 068
दि. 07.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'सनातन धर्म में बसती है भारत की आत्मा, राम का मतलब होता है राष्ट्र', प्रयागराज में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंहल की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

(जीएनएस)।

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार 6 जुलाई को प्रयागराज में थे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और सनातन धर्म की आत्मा राम हैं। मुख्यमंत्री ने यमुना तट पर नवनिर्मित प्रेरणा पार्क के उद्घाटन किया। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंहल की प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया।

'एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा'

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। बोले, आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण, आज भारत की राजनीति के महान विभूति के 125 वर्ष पूरे हुए है जिनका जीवन भारत की एकता अखंडता को समर्पित था। एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, यह कहकर अपने जीवन का बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद देश भर के लिए प्रेरणा हैं।

'पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने एक साथ तीन महान विभूतियों के प्रतिमाओं का निर्माण कर बड़ा काम किया है। श्यामा प्रसाद अखंड भारत के स्वप्नद्रष्टा थे। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान को देने की बात उठी तो डा. मुखर्जी ने इस खिलाफ शंखनाद किया था और कहा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे।

श्यामा प्रसाद के बलिदान को याद किया

श्यामा प्रसाद ने देश की अखंडता के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने किन परिस्थितियों में काम किया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मंत्री बने थे। देश के हित उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और भारतीय जन संघ की स्थापना की। आज कश्मीर में उनके प्रयास के चलते आज उस बंगाल में बीजेपी का कमल खिल रहा है। समृद्धि, सुशासन और सुरक्षा का कमल खिल रहा है। धारा 370 समाप्त हुई। गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से कश्मीर को भारत में उसी तरह मिलाया जैसे अन्य राज्य हैं।

अटल बिहारी व सिंघल के कार्यों पर की चर्चा

बोले कि डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो पाया है। भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी ने छह दशकों तक काम किया लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन पर कोई दाग नहीं लगा। अशोक सिंघल का जीवन राष्ट्र को समर्पित था। राम जन्मभूमि देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। देश के सभी संतों को एक मंच पर लाने का काम अशोक सिंघल ने किया।

समता की भूमि है प्रयागराज'

बोले, प्रयागराज समता की भूमि है, इसकी पौराणिक महत्ता है, भारद्वाज ने यहां साधना की थी। जब वन गए और वापस आए तो भगवान राम ने महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लिया। डबल इंजन सरकार ने प्रयागराज में भारद्वाज ने उनकी भव्य प्रतिमा और मंदिर का निर्माण किया।

'खेलों में नंबर-1 बनने की राह पर उत्तर प्रदेश', खिलाड़ियों के नाम सीएम योगी का खास संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के नाम संदेश जारी करते कहा कि यूपी खेलों में नंबर-1 बनने की ओर बढ़ रहा है और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में खेलों के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की लगातार मिल रही सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अब विकास के साथ-साथ खेलों में भी देश का नंबर-1 राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है.

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में खेलों के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष पाती लिखी. मुख्यमंत्री ने कहा, "मैदान की मिट्टी जीत-हार नहीं, बल्कि हर बार उठकर आगे बढ़ना सिखाती है."

उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश अब

विकास के साथ-साथ खेलों में भी देश का नंबर-1 राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लेख में लिखते हैं, "प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यूपी की पुरुष टीम पहली बार चैंपियन बनी. राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 20 पदक जीतकर उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रचा. अंडर-18 हॉकी एशिया कप विजेता भारतीय टीम में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया."

मुख्यमंत्री ने दीप्ति शर्मा, प्रवीण कुमार, अन्नू रानी, सिमरन शर्मा और वंशिका अग्रवाल की उपलब्धियों पर प्रदेश को गर्व होने की बात कही. उन्होंने कहा कि चैंपियन एक दिन में नहीं बनते और खेल संस्कृति भी रातों-रात विकसित नहीं होती.

सीएम योगी ने आगे कहा, "प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के कौशल विकास, आधुनिक प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस कर रही है. हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं. प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जबकि मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार किया जा रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है. खिलाड़ियों को वर्ल्ड लेवल ट्रेनिंग, आधुनिक सुविधाएं और सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि खेल नशे जैसी बुराइयों से बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण, सकारात्मक सोच और टीम भावना का सबसे बड़ा माध्यम हैं.

'भारत हमारे साथ', नेतन्याहू ने उड़ाई जेडी वेंस के दावे की धज्जियां, क्यों भिड़े दोनों नेता?

इजरायल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के बीच इन दिनों तनाव खुलकर सामने आ रहा है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का नाम लेकर बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अमेरिका ही इजरायल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सहारा है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजरायल के पास अमेरिका के अलावा भी कई मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं और भारत उनमें सबसे अहम देशों में शामिल है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि उनके पास भारत जैसा "छोटा सा देश" भी दोस्त है।

मुंबई में रेड अलर्ट, 17 उड़ानें रद्द, लोकल बाधित, जमीन से लेकर आसमान तक यातायात ठप्प

(जीएनएस)।

मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्टऊ ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरे शहर में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ हाईटाइड के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 200 से ज्यादा उड़ानें देर से चल रही हैं और कई विमानों को दूसरे शहरों की डायवर्ट किया गया है। लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हैं और कई मार्गों पर पानी भरने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

टर्‌ फ्रल्ल२

भारी बारिश के चलते मुंबई के निचले इलाकों में गंभीर जलभराव (वॉटरलॉगिंग) की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें जलमग्न होने से यातायात लगभग ठप हो गया है। प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी गई है। सीएम ने मुंबई के नागरिकों से अपील की है कि वे बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और विशेष रूप से समुद्र तटों से दूर रहें।

महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के आपदा नियंत्रण कक्ष (डिजास्टर कंट्रोल रूम) में हाई लेवल मीटिंग की। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से मुंबई और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन और चेतावनियां जारी कीं। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के खतरों को देखते हुए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है।

'ईडी-सीबीआई नहीं, एसआईटी क्यों?': 'राम मंदिर दान' पर अखिलेश का बड़ा दावा, बोले- दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई में दब गई जांच

(जीएनएस)।

लखनऊ, अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि पैसे को देखकर लोग पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे हैं। हमारा मानना है कि जो कोई भी भगवान राम के जीवन का अध्ययन करता है, वह 'लक्ष्मण रेखा' (मयार्दा की रेखा) के बारे में जानता है फिर भी यहां हर किसी ने 'मयार्दा' की सीमाओं को लांघ दिया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर परोक्ष रूप से तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले की जांच को सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बजाय एक विशेष जांच दल (एसआईआटी) को सौंप दिया गया, क्योंकि पार्टी के भीतर 'आंतरिक सत्ता संघर्ष' चल रहा है।

अखिलेश यादव ने बीजेपी का नाम लिए बिना संकेत दिया कि उसके पास सत्ता के दो केंद्र हैं- एक लखनऊ में और दूसरा दिल्ली में। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को संभालने का तरीका इसी आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित था।

अखिलेश ने कहा कि चढ़ावा, दान और योगदान चोरों के एक गिरोह के हाथ लग गया है। वे जनता के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, वे जनता के आक्रोश से डरे हुए हैं, यही वजह है कि वे घरों के अंदर दुबके हुए

जब पत्रकारों ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का जिक्र किया, तो अखिलेश यादव ने अपनी बात को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जुड़ी बात को ठीक से नहीं समझा। मैं सत्ता संघर्ष की बात कर रहा था। अगर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स इसमें शामिल होते, तो जांच की कमान किसके हाथ में होती? दिल्ली नेतृत्व के कुछ भी कदम उठाने से पहले, लखनऊ गुट ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? यह एसआईटी क्या है? इसकी रिपोर्ट किसे सौंपी गई? आप इस साधारण से सच को भी नहीं समझ पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि जांच एजेंसी का चुनाव खुद सत्ताधारी दल के भीतर के आंतरिक राजनीतिक समीकरणों को दशार्ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "पैसे को देखकर लोग पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे हैं। हमारा मानना है कि जो कोई भी भगवान राम के जीवन का अध्ययन करता है, वह 'लक्ष्मण रेखा' (मयार्दा की रेखा) के बारे में जानता है फिर भी यहां हर किसी ने 'मयार्दा' की सीमाओं को लांघ दिया है।

इस बीच, राम मंदिर दान विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी ने सपा प्रमुख पर कड़ा पलटवार किया है।

अखिलेश यादव की आलोचना का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही विपक्षी दलों पर लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

ब्रजेश पाठक ने कहा, 'यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, इस देश के लोग और सनातन धर्म का हर अनुयायी जानता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। वे तो यहां तक दावा करते थे कि यह भी निश्चित नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तर्क दिया था कि राम लला का जन्मस्थान स्थापित नहीं हुआ है।'

उपमुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दलों ने भगवान राम के खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं, जिन्हें भगवान राम कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें अपने बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

वेस्ट बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी, टीएमसी सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई थीं सीटें

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में खाली हुई राज्यसभा की तीन सीटों पर संसद के नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई (सोमवार) को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन सीटों पर उपचुनाव आगामी 24 जुलाई 2026 को आयोजित किए जाएंगे।

यह उपचुनाव उन तीन महत्वपूर्ण सीटों को भरने के लिए कराया जा रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन प्रमुख सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। आयोग ने बताया है कि चुनाव के दिन मतदान की प्रक्रिया सुबह 9:00 बजे से प्रारंभ होकर शाम 4:00 बजे तक चलेगी, जिसके तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू होगी।

यह निर्वाचन प्रक्रिया राज्यसभा की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के नियमों के तहत आयोजित की जा रही है। इस्तीफा देने वाले सांसदों में सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश

चिक बराइक शामिल हैं। इनके जाने से उच्च सदन में बंगाल के प्रतिनिधित्व में खालीपन आया है, जिसे दूर करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है।

इस्तीफा देने वाले तीनों सांसदों का पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में अलग-अलग प्रभाव रहा है। सुखेंदु शेखर रॉय पार्टी के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, जो कई अहम राष्ट्रीय मसलों पर संसद में टीएमसी की आवाज रहे हैं। उनके स्थान पर किसी नए अनुभवी चेहरे को लाना पार्टी के लिए एक वैचारिक और रणनीतिक निर्णय होगा।

वहीं, सुष्मिता देव मूल रूप से असम की वरिष्ठ राजनेता रही हैं, जिन्हें टीएमसी ने अपनी राष्ट्रीय विस्तार योजना के तहत उच्च सदन में भेजा था। उनके इस्तीफे के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी बाहरी चेहरे को दोबारा चुनती है या फिर इस बार बंगाल के किसी स्थानीय नेता को प्राथमिकता देती है।

वाह रे पाकिस्तान! अग्निकांड में 11 से साल के बच्चे को बनाया बलि का बकरा, हादसे में गईं थी 72 जानें

पाकिस्तान के कराची से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। इसी साल जनवरी के महीने में कराची के मशहूर गुल प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में

भीषण आग लगी थी, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में 11 साल के एक बच्चे को मुख्य आरोपी बनाया है। अब इस बच्चे को अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह दर्दनाक हादसा 17 जनवरी 2026 को कराची के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाके सदर में एम. ए. जिन्ना रोड पर स्थित गुल प्लाजा में हुआ था।

'10 मिनट में पोस्ट हटाओ', BJP MP को अखिलेश ने दी अल्टीमेटम, निशिकांत दुबे बोले- राम भक्त पर गोली किसने चलवाई?

(जीएनएस)।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान की कथित हेराफेरी का मामला अब एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक रंग ले चुका है। इस पूरे विवाद की आंच अब सीधे समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेजतर्रार सांसद निशिकांत दुबे के बीच एक बड़े 'ट्विटर वॉर' (सोशल मीडिया जंग) में बदल गई है।

बात इतनी बढ़ गई है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सरेआम सिर्फ 10 मिनट के भीतर अपना पोस्ट हटाने का अल्टीमेटम दे दिया और ऐसा न करने पर सीधे नामजद एफआईआर दर्ज कराने की खुली चेतावनी दे डाली।

दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने अदालत जाने की बात कहकर इस जंग को और तेज कर दिया है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है और 'टिन्नू-टीपू' के इस ताने के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है।

इस पूरे सियासी घमासान की शुरूआत झारखंड के गोड्‌डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के साथ अखिलेश यादव की एक तस्वीर साझा करते हुए निशिकांत दुबे ने तंज कसा और लिखा, 'टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था?' (बता दें कि 'टीपू' अखिलेश यादव का घरेलू नाम है)।

इस पोस्ट को देखते ही सपा प्रमुख का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सोमवार (06 जुलाई) शाम करीब 4:17 बजे अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाबी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मयार्दा और संसदीय परंपराओं का लिहाज करते हुए वह बीजेपी सांसद को अपनी यह 'झूठी पोस्ट' हटाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दे रहे हैं।

अगर तय समय में यह पोस्ट डिलीट नहीं हुई, तो वह तुरंत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अखिलेश ने उन सभी लोगों को भी चेतावनी दी जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया है कि वे इसे हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, वरना कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। अखिलेश यादव की इस कानूनी धमकी पर निशिकांत दुबे ने भी तुरंत और बेहद तीखा पलटवार किया। उन्होंने बिना किसी डर के एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है? 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा।' निशिकांत दुबे ने अपने इस जवाब से न सिर्फ अखिलेश के अल्टीमेटम को ठेंगा दिखा दिया, बल्कि पुराना चुनावी और राजनीतिक मुद्दा उछालते हुए मुलायम सिंह यादव के दौर में कारसेवकों पर हुई फायरिंग की घटना की याद दिलाकर मामले को पूरी तरह ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया।

राममंदिर में चोरी से आहत महंत नृत्यगोपाल दास जताया गहरा दुख, दोषियों को कड़ी सजा की मांग की

(जीएनएस)।

अयोध्या,

श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने श्रीरामलला सरकार के मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोमवार को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि श्रीरामलला सरकार के मंदिर में हुई चोरी से वे अत्यंत आहत हैं। जिसने भी यह पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी होगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने निजी या राजनीतिक हितों के लिए इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को सख्त से सख्त दंड देने की मांग की।

शंकराचार्य द्वार पर रहा कड़ा पहरा

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर आद्य शंकराचार्य द्वार पर कड़ा पहरा रहा। बैठक पहली बार राम मंदिर परिसर में हुई। बैठक के लिए सभी ट्रस्टियों ने शंकराचार्य द्वार से ही मंदिर में प्रवेश किया। द्वार पर सुबह से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तनाती कर दी गई थी। शंकराचार्य द्वार की ओर जाने वाली एक लेन को बंद कर दिया गया था। बैरीकेडिंग लगाकर लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई थी।

'मैं अमिताभ हूं, यूपी से और अयोध्या जी में जमीन लेनी है', जब 3 बजे रात अभिनंदन लोढ़ा को बिग बी का आया था फोन

(जीएनएस)।

भारत के पवित्र स्थलों में से एक अयोध्या नगरी में फिल्मी सितारे भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट खूब कर रहे हैं जिनमें से एक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अब रियल एस्टेट डील करने वाले अभिनंदन लोढ़ा ने उस रात का किस्सा सुनाया जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें रात 3 बजे फोन करके जमीन खरीदने की बात कही थी।

अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए अमिताभ का कॉल

अयोध्या जैसे शहर अब आस्था के केंद्र के साथ-साथ रियल एस्टेट निवेश के लिए भी लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। आम पब्लिक ही नहीं, इस शहर में निवेश के लिए फिल्मी सितारे भी आगे बढ़ रहे हैं और इनमें से एक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये तो आप सभी जानते हैं लेकिन इस डील से ठीक पहले क्या कुछ हुआ था, इस बारे में 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' (HoABL) के फाउंडर और चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने दिलचस्प वाकया शेयर किया है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कैसे देर रात खुद उन्हें फोन कर अयोध्या में जमीन खरीदने की इच्छा जताई थी।

लोढ़ा ने बताया कि साल 2023 में वह ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां तड़के करीब 3 बजे उनके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल आए। इसके बाद एक मेसेज मिला, जिसमें अमिताभ बच्चन की विनम्रता देख वे हैरान रह गए। इस

मेसेज में लिखा था, 'मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, जब समय मिले तो कृपया मुझे कॉल करें।'

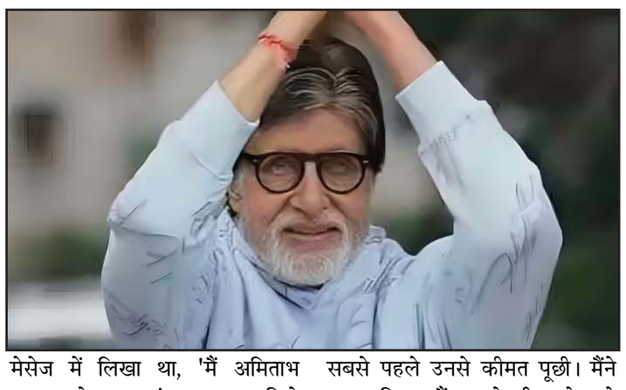

'सुनते ही मैं उठकर खड़ा हो गया तुरंत अमिताभ बच्चन को फोन किया'

उन्होंने कहा, 'यह सुनते ही मैं उठकर खड़ा हो गया तुरंत अमिताभ बच्चन को फोन किया।' 'हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया नेक्स्ट रियल एस्टेट समिट 2026' में इस घटना को याद करते हुए लोढ़ा ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा बिग बी की सादगी और विनम्रता ने इम्प्रेस किया।

बच्चन साहब ने सबसे पहले उनसे कीमत पूछी

लोढ़ा ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, 'अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है। मैंने उनसे कहा कि हम उनके लिए ये अरेंज कर देंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'बच्चन साहब ने सबसे पहले उनसे कीमत पूछी। मैंने जवाब दिया- मैं आपसे कीमत के बारे में कैसे बात कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि वे 15,000 सक्वॉयर फुट जमीन खरीदना चाहते हैं और मैंने उनसे कहा कि इतनी जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये के आसपास होगी और अगले ही दिन उन्होंने मुझे 15 करोड़ रुपये भेज दिए।'

अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है। बच्चन साहब ने सबसे पहले कीमत पूछी। मैंने जवाब दिया- मैं आपसे कीमत के बारे में कैसे बात कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि वे 15,000 सक्वॉयर फुट जमीन खरीदना चाहते हैं और मैंने उनसे कहा कि इतनी जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये के आसपास होगी और अगले ही दिन उन्होंने मुझे 15 करोड़ रुपये भेज दिए।

35 करोड़ रुपये में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी

मार्च 2026 में अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा किया और उन्होंने लङ्गअइछ से करीब 35 करोड़ रुपये में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह अयोध्या में उनका तीसरा और HoABL के साथ चौथा इन्वेस्टमेंट था। यह जमीन कंपनी के 75 एकड़ में फैले 'द सरयू' प्रोजेक्ट के पास स्थित है।

40 करोड़ रुपये में 25,000 स्क्वॉयर फुट का प्लॉट खरीदा था

बता दें कि इससे पहले मई 2025 में उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपये में 25,000 स्क्वॉयर फुट का प्लॉट खरीदा था। वहीं, 2024 में उन्होंने 'द सरयू' प्रोजेक्ट में 10,000 स्क्वॉयर फुट का प्लॉट करीब 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था।

कृति सैनन और कार्तिक आर्यन ने भी अपने पैसे लगाए हैं

अयोध्या के अलावा अमिताभ बच्चन लङ्गअइछ के 'सोल दे अलीबाग' प्रोजेक्ट में भी करीब 10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। यहां उन्होंने 10,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। इसी प्रोजेक्ट में कृति सैनन और कार्तिक आर्यन ने भी अपने पैसे लगाए हैं और यहां निवेश किया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस ने मांगी, मंगलवार को सुनवाई

राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों की पुलिस ने 7 दिन की और कस्टडी रिमांड मांगी है। पुलिस इनसे और पूछताछ करके जानकारी जुटाना चाहती है। वहीं, सोमवार को राम मंदिर की बैठक हुई।

(जीएनएस)।

अयोध्याः राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने कोर्ट से तीन प्रमुख आरोपियों, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की है। अयोध्या कोर्ट मंगलवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई कर फैसला सुनाएगी। ये तीनों आरोपी उन आठ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में रखा गया है।

पुलिस अब इन तीनों से विस्तार से पूछताछ करना चाहती है। पुलिस का कहना है कि कस्टडी रिमांड मिलने पर वह आरोपियों से चोरी के पूरे मामले, चढ़ावे की रकम कहां-कहां गई और अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी हासिल करेगी। आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस यह जानना चाहती है कि फोन से क्या आरोपियों ने कुछ डेटा डिलीट तो नहीं किया।

दान पेटियों में की हेराफेरी

राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हैं। इन सभी पर राम मंदिर की दान पेटियों से नकदी और कीमती सामान की हेराफेरी करने की साजिश रचने का आरोप है।

अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख मिले

अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपये की बड़ी रकम बरामद की गई। पुलिस ने जांच के दौरान उसके पास से डॉलर और कुछ अन्य मुद्रा भी बरामद की। उसके परिसर से जब्त की गई नकदी में 500 रुपये के 3,600 से अधिक नोट, 200 रुपये के 500 से अधिक नोट और 10, 20, और 50 रुपये के नोट शामिल हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसने यह सब मंदिर में चढ़ावे से अर्जित किया था।

करुणेश पांडे के पास से 18 लाख मिले

करुणेश पांडे के पास से 500, 200, 50, 10 और 20 रुपये के नोट बरामद किए गए। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने उसके पास से कुल 18.07 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति की तेजी से जांच की जा रही है। राजस्व विभाग से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के जमीन रिकॉर्ड मांगे गए थे, जिनमें से अब तक करीब 20 लैंड पार्सल के रिकॉर्ड पुलिस को मिल चुके हैं। इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

SIT को अतिरिक्त समय दिया गया

जांच में यह देखा जा रहा है कि संबंधित संपत्तियां कब खरीदी गईं और आरोपियों का राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ाव कब हुआ। पुलिस के लिए इन दोनों तारीखों का मिलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम को जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

'जिनको अपने दान की सत्यता जाननी है, कभी भी अयोध्या आ सकता है', राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से चढ़ावे को लेकर क्या दी गई जानकारी

(जीएनएस)।

राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर ट्रस्ट ने सोमवार को बैठक की। बैठक करीब तीन घंटे तक चली। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रस्ट ने हरेक बात की जानकारी दी।

(जीएनएस)।

अयोध्याः राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक करीब तीन घंटे चली। इसके बाद ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ट्रस्ट ने हरेक सवाल का जवाब दिया। ट्रस्ट ने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को बनाया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों की बैठक सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुई। इसमें प्रमुख रूप से दानपात्रों से प्राप्त राशि की गणना की प्रक्रिया में

अनियमितता, उसकी जांच और कार्रवाई, महामंत्री और एक न्यासी के न्यासी पद से त्यागपत्रों, मीडिया में चल रही चर्चाओं, भावी अन्तरिम व्यवस्थाओं आदि विषयों पर विचार हुआ।

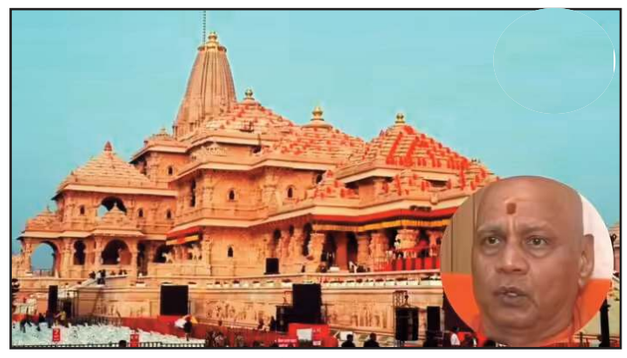

2020 में ट्रस्ट की स्थापना के बाद छह वर्ष से कम के अल्पकाल में प्रभु श्री रामलला के भावी और अप्रतिम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक कार्य सम्पूर्ण हुआ। इसी अवधि में मुख्य मंदिर एवं परकोटे में बने समस्त मंदिरों में प्राण-प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण और श्रीराम यंत्र की स्थापना के महती कार्य प्रभु कृपा से सानंद और शास्त्रीय विधि-विधान से संपन्न हुए। न्यास इस सांस्कृतिक धरोहर के निर्माण और अनेक धार्मिक उत्सवों में सहयोगी सम्पूर्ण हिन्दू समाज, श्रमिकों, अभियन्ताओं, शिल्पकारों, वास्तुविदों और केंद्रीय व राज्य सरकारों का हार्दिक आभार मानता है।

31 मार्च तक 582 करोड़ रुपये चढ़ावा मिला

ट्रस्ट ने कहा कि निधि समर्पण अभियान एवं कॉर्पस दान के माध्यम से प्राप्त कुल राशि 3264 करोड़ रुपये में से 2370 करोड़ रुपये निर्माण एवं पूंजीगत व्यय में उपयोग की गई है। प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च, 2026 तक कुल चढ़ावा 582 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें से 391 करोड़ रुपये की राशि संचालन व्यय में उपयोग ली गई। शेष राशियां बैंक खातों में उपलब्ध है। ये समस्त वितीय सूचनाएं समय-समय पर ट्रस्ट ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित हुई

चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता से न्यासीगण आहत एवं चिंतित हैं और इस दुर्भाग्यकारी प्रकरण पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं। इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर पाया है कि ट्रस्ट के अधिकारियों ने अनियमितता के संज्ञान में आने पर प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने के बाद उतर-प्रदेश शासन से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया। ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष, व्यापक और तथ्यपरक जांच हो सके। किसकी क्या भूमिका रही, किन लोगों की संलिप्तता है और किसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए-इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल जांच के आधार पर ही संभव था। इसी उद्देश्य से ऐसे जांच दल के गठन के अनुरोध की पहल की गई।

ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम सामने आए। जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले, उनके विरुद्ध ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारियां भी हुईं। अब पूरा मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ट्रस्ट का स्पष्ट मत है कि जो भी दोषी हो, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होकर कठोरतम दंड मिलना चाहिए। एसआईटी का कार्यक्षेत्र सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुझाव देना भी है कि ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में क्या आवश्यक सुधार करने चाहिए, जिससे व्यवस्था और अधिक सुदृढ़, मजबूत एवं पारदर्शी हो सके।

चंपत राय और अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है, जिन्हें आज ट्रस्ट की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए नैतिक आधार पर दिए दोनों के त्यागपत्र को स्वीकार किया है। साथ ही ट्रस्ट ने गोपाल नगरकोटे (गोपाल राव) का नाम विशिष्ट आमंत्रित सदस्य सूची से हटाने का निर्णय किया है। ट्रस्ट का मानना है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा और तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है।

कुछ लोग लगातार भ्रम फैला रहे हैं

ट्रस्ट ने प्रबंधन एवं संचालन की पद्धति और प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और एसआईटी से अपेक्षित अनुशंसाओं के अतिरिक्त विशेषज्ञों से भी स्वतंत्र परामर्श लेने का सुझाव दिया है, जिससे मंदिर प्रबंधन की एक आदर्श, कुशल और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो सके, जो इस क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण बने। कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्रीरामलला मंदिर, श्रीराम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आधारहीन आरोप जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सत्य सामने लाना नहीं, बल्कि निरंतर भ्रम फैलाना है।

तमाम विवादों और दुष्प्रचार के बावजूद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एवं श्रद्धा में कमी नहीं आई है। मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन पूर्ववत निरंतर जारी है। यह इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन व भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या

2926 भेंटें मिली हैं

नकद राशि के अतिरिक्त अनेक श्रद्धालुओं ने वस्तु के रूप में प्रभु श्री रामलला को भेंट अर्पित की हैं। ऐसी कुल 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं, जो समस्त, तिथि अनुसार, सम्पूर्ण विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज हैं और उनका भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा आंतरिक अंकेक्षक के नाते प्रति वर्ष किया जाता है। काउंटर पर ऐसी भेंट देने वाले समस्त श्रद्धालुओं को रसीद दी गई हैं और काउंटर के अतिरिक्त दी गई भेंट के लिए भी उन समस्त श्रद्धालुओं को रसीद दी गई है, जिन्होंने दानदाता का विवरण दिया। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी अपनी दी हुई भेंट का उपयोग जानना और सत्यापन करना चाहें, वे कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि व समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और प्रभु श्री रामलला के दर्शन के साथ अपनी भेंट का सत्यापन कर सकते हैं।

चांदी को गलाकर छड़ें बना दी गईं

चांदी की वस्तुओं को भारत सरकार की टकसाल (मिंट) में गला कर छड़ें बनाई गई हैं, जिनके मूल स्वरूप का विवरण फोटो व वजन सहित उपलब्ध है। गलाने के पश्चात चांदी की शुद्धता और कुल वजन के टकसाल के प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध हैं।

ट्रस्ट का आग्रह है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या पत्रकार के पास मंदिर से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनियमितता के ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय एसआईटी और संबंधित जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जाए। जांच एजेंसियां प्रमाणों के आधार पर अवश्य कार्रवाई करेंगी।

न्यास की बैठक में नए महामंत्री की नियुक्ति होने तक ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री नियुक्त किया गया है। न्यास ने एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो ट्रस्ट को उपयुक्त नामों की अनुशंसा करेगा।

100 दलित उम्मीदवारों के साथ अखिलेश यादव का 'अयोध्या मॉडल' फिर सफल होगा क्या?

(जीएनएस)।

लखनऊ,

अखिलेश यादव आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में लोकसभा चुनाव के कारगर नुस्खे फिर आजमाने जा रहे हैं. लोकसभा चुनाव में ढऊअ के सफल प्रयोग के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उसे विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है - और, बीजेपी से सीधे मुकाबले के लिए निशाना बीएसपी नेता मायावती के वोटर पर टिकी है.

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर मौके पर ढऊअ (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) फैक्टर का जिक्र करते हुए उसकी अहमियत समझाते रहे हैं. अखिलेश यादव को बीएसपी या मायावती पर सीधा हमले से परहेज करते भी देखा जाता रहा है, लेकिन अब मिजाज बदल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अखिलेश यादव को लगता है कि दलित वोट बैंक के एक हिस्से को अगर बीएसपी की चुनावी रणनीति समझाने की कोशिश की जाए, तो वे समाजवादी पार्टी का साथ दे सकते हैं - और, अगर ऐसा संभव हुआ तो बीजेपी से मुकाबला थोड़ा आसान हो सकता है.

समाजवादी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की ही तरह सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने का प्लान कर रही है. लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा सीट) के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे करके बीजेपी को टार्गेट करते रहे हैं, लगता है आने वाले चुनाव में भी वैसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है - सवाल है कि यूपी चुनाव में 100 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी मायावती के वोटर को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है?

समाजवादी पार्टी का PDA विस्तार अभियान

अखिलेश यादव लगता है अपनी छवि बदलने की कोशिश में लग गए हैं. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को लोक पिछड़ों के नेता मानते थे, लेकिन अखिलेश यादव की यादव समुदाय के नेता की छवि बनने लगी थी. बीजेपी विरोध के नाम पर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय के भी वोट मिल जाते हैं. आने वाले यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की जो रणनीति सामने आ रही है, मालूम होता है कि दलित वोट बैंक में ढंग से सेंध लगाने की कोशिश है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी दलित वोटों को ऐसे समय साधने की कोशिश कर रही है, जब मायावती बीएसपी के लिए फिर से दलित और ब्राह्मण वोटों की सोशल इंजीनियरिग पर काम कर रही हैं. समाजवादी पार्टी और उसकी गठबंधन साथी कांग्रेस एक साथ आरोप लगाते हैं कि बीएसपी की चुनावी रणनीति बीजेपी की मदद के लिए होती है.

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी आने वाले यूपी चुनाव में 100 दलित उम्मीदवार उतारने जा रही है. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं. सुरक्षित सीटों पर तो हर पार्टी के दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी 14 अनारक्षित सीटों पर भी दलित नेताओं को टिकट देने की योजना पर काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश की 403 में से 100 सीटों पर दलित नेताओं को टिकट देने की रणनीति असल में अखिलेश यादव के पीडीए का विस्तार कार्यक्रम है - अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी के दलित प्रोजेक्ट का मकसद क्या है?

समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब है, दलित समुदाय को संदेश भेजने के अलावा इसका मकसद एक व्यापक नैरेटिव तैयार करना भी है, और यह कि समाजवादी पार्टी अब अपनी यादव-मुस्लिम पार्टी वाली छवि से उबर रही है. समाजवादी पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना है, यह कदम उठाए जाने का मकसद यह नैरेटिव गढ़ना है कि समाजवादी पार्टी दलितों को आरक्षित सीटों से भी ज्यादा हिस्सेदारी देने को तैयार है... हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही किया था और हमें इसका फायदा मिला था.

देखा जाए, तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ढऊअ एक्सपेरिमेंट सफल रहा. 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट से दो दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया था, मेरठ और फैजाबाद. फैजाबाद लोकसभा सीट तो अवधेश प्रसाद ने जीतकर समाजवादी पार्टी को थमा दिया, लेकिन मेरठ में सुनीता वर्मा रामायण में श्रीराम का किरदार निभाने वाले बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल से महज 10,585 वोटों से हार गई.

अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सामान्य सीटों पर अपने दलित उम्मीदवारों को आजमाने जा रही है?

समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, हम दलित समुदाय के उन उम्मीदवारों को चुनने जा रहे हैं जो सामान्य सीटों पर लड़ सकें... हमारा लक्ष्य इस बार दलितों को 100 सीटें देना है, लेकिन यह मजबूत और उपयुक्त उम्मीदवार मिलने पर ही निर्भर करेगा... जिन सामान्य सीटों पर हम दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, वे मुख्य रूप से ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी पहले से बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है.

क्या मायावती के प्रति अखिलेश यादव का रुख बदलने वाला है?

ढऊअ में दलित विस्तार योजना का कोई नकारात्मक असर न पड़े, इसका भी इंतजाम पहले से ही किया जा रहा है. एक मुस्लिम समाज से आने वाले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'अखिलेश जी ने यादव और मुस्लिम नेताओं को साफ तौर पर बताया है कि इस बार समाजवादी पार्टी 2024 वाला फॉमूर्ला ही अपनाएगी, और दोनों समुदायों को ज्यादा टिकट नहीं दिए जाएंगे... सरकार बनने के बाद ऐसे नेताओं को विधान परिषद के जरिए जगह दी जाएगी.'

और इसके साथ ही अखिलेश यादव धीरे धीरे आक्रामक होने लगे हैं. बीते चुनावों में अखिलेश यादव को बीएसपी वोटर और मायावती के प्रति काफी नरम देखा जा चुका है. संभव है आने वाले चुनाव में ये सब न देखने को मिले. हाल के ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने दलित समुदाय से वोट मांगते वक्त अपनी तरफ से हकीकत समझाने की भी कोशिश की. बोले, बीएसपी चाहे बीजेपी के साथ खुलकर हो या छिपकर, बीएसपी को वोट देना अपना वोट गंवाना है.

बीएसपी पर अखिलेश यादव का यह बदला स्टैंड तो यही बता रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले चुनाव में दलित वोट हासिल करने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले हैं. समाजवादी पार्टी के दलित फेस राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के मुताबिक, समाजवादी पार्टी को दलित वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करने का पक्का यकीन है. कहते हैं, मैं बीएसपी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि बीएसपी आखिरकार बीजेपी की मदद करने वाली है. मौजूदा राजनीतिक माहौल में कोई भी राजनीतिक पार्टी हाथ पर हाथ रखे वोट पाने की उम्मीद नहीं कर सकती, जैसा बीएसपी कर रही है... हमें दलित समुदाय से बीजेपी विरोधी वोट मिलेंगे... दलितों को यह एहसास हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस की मूल मानसिकता दलित विरोधी है, जो उनके मनुवादी एजेंडे में झलकती है.

उत्तर प्रदेश में 21 फीसदी दलित आबादी है, और वही मायावती की राजनीति का मजबूत आधार है. दलितों के साथ ब्राह्मण वोटर को जोड़कर मायावती 2007 में अकेले दम पर बीएसपी की सरकार बना चुकी हैं, और एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का वही फॉमूर्ला अपनाने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन, हालात अच्छे नहीं रह गए हैं. 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी. और, 2017 में 22.23 फीसदी रहा उसका वोट शेयर गिर कर 12.88 फीसदी पहुंच गया था. 2024 के आम चुनाव में तो बीएसपी का वोट शेयर लुढ़क कर 9.4 फीसदी ही रह गया, जबकि 2019 में बीएसपी का वोट शेयर 19.43 फीसदी दर्ज किया गया था - लगता है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मायावती की गिरती लोकप्रियता का फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

खामेनेई की अंतिम यात्रा में जनसैलाब ने एतिहासिक रूप से विशाल स्वरूप लिया

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के साथ पश्चिम एशिया की राजनीति का एक ऐतिहासिक अध्याय समाप्त हो गया।

तीन दशकों से अधिक समय तक ईरान का नेतृत्व करने वाले खामेनेई केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि करोड़ों ईरानियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और देश की स्वतंत्र विदेश नीति के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे।

उनके अंतिम दर्शन और राजकीय विदाई समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपने समर्थकों के बीच कितने लोकप्रिय थे। राजधानी तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महिलाएं, पुरुष, युवा, बुज़ुर्ग, छात्र, सैनिक और आम नागरिक–हर वर्ग के लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों तथा विशेष प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने भी इस समारोह को विश्व राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल कर दिया।

इतिहास में वुछ ही ऐसे नेता हुए हैं जिनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब ने इतना विशाल स्वरूप लिया हो। चाहे समर्थक हों या आलोचक, इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और वैचारिक दृढ़ता से ईरान के राजनीतिक और धरमिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। उनके नेतृत्व में ईरान ने अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, युद्ध जैसी परिस्थितियों और वूटनीतिक दबावों का सामना किया, फिर भी अपनी नीतियों और राष्ट्रीय संप्रभुता पर दृढ़ रहने का प्रयास किया।

उनके समर्थकों के लिए वे केवल एक सर्वोच्च नेता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, प्रतिरोध और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक थे। यही कारण है कि उनके निधन के बाद पूरे ईरान में शोक की ऐसी लहर देखने को मिली, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आर्कषित किया।

यह कहना कठिन है कि भविष्य में कोई अन्य नेता उनके समान प्रभाव, स्वीकार्यता और वैचारिक पहचान स्थापित कर पाएगा। हर युग अपने साथ वुछ ऐसे व्यक्तित्व लेकर आता है जो समय की सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई भी ऐसे ही नेताओं में गिने जाएंगे, जिनका प्रभाव केवल उनके जीवनकाल तक सीमित नहीं रहेगा।

आने वाले वर्षों में ईरान नई चुनौतियों और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन खामेनेई की स्मृतियां, उनके भाषण, उनके निर्णय और उनके नेतृत्व का प्रभाव देश की राजनीति, धरमिक संस्थाओं और राष्ट्रीय विमर्श में लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। उनके समर्थकों के लिए वे सदैव "रहबर–ए–इंकलाब" रहेंगे, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

इतिहास नेताओं का मूल्यांकन समय के साथ करता है, लेकिन यह र्निविवाद है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान के आधुनिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है, पर उनकी विरासत और स्मृतियां ईरान के इतिहास में लंबे समय तक जीवित रहेंगी।

यूपी परिवहन विभाग में भर्ती घोटाले पर सीएम योगी सख्त, कंपनियों के खिलाफ जांच और ब्लैकलिस्ट की तैयारी

(जीएनएस)।

लखनऊः पिछले चार माह से परिवहन विभाग की नौकरी से निकाले गए पीड़ित विभाग के चक्कर काट रहे हैं. न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली कंपनियों की अंधेरगर्दी की दर्जनों शिकायतें भी परिवहन विभाग के अधिकारियों से लेकर परिवहन मंत्री तक की गई, लेकिन इन शिकायतों का समाधान करने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

जब कहीं से पीड़ितों को न्याय की उम्मीद नजर नहीं आई तो वे सोमवार को सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे.

जानकारी देते पीड़ित. (श्रींङ्क उ३१्रि३ः एळश ईं१३)

मुख्यमंत्री की सख्ती से हड़कंपः यहां पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या सुनी और तत्काल अधिकारियों को जांच करने के लिए निर्देशित किया. इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी जो पीड़ितों की शिकायत सुनने तक को तैयार नहीं थे उनके फोन खुद ही पीड़ितों के पास आने लगे. अब उन्हीं अधिकारियों ने पीड़ितों की शिकायत सुनने के लिए याद किया है. मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब पीड़ित बेरोजगारों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में फरियादी तब शिकायत लेकर पहुंचते हैं जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है. दौड़ते–दौड़ते थक जाते हैं.

नौकरी के नाम पर लाखों की ठगीः मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के बाद ही उनमें न्याय की उम्मीद जागती है. ऐसा ही परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों के साथ हुआ. परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जिन तीन कंपनियों सिल्वर टच, फोकॉम डॉट नेट और रोजमार्टा को ठेका दिया, उन कंपनियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स पॉलिसी लागू करने वाली सरकार में भ्रष्टाचार की इंतिहा कर डाली. प्रदेश भर में तमाम कर्मचारियों को पहले नौकरी के नाम पर पैसा लेकर रखा और इसके बाद मनमानी ढंग से किसी को एक माह तो किसी को दो माह नौकरी करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया.

कंपनियों के प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोपः 50 कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए ही नौकरी से हटा दिया गया. कर्मचारी बेरोजगार हुए तो उन्होंने कंपनियों के भ्रष्टाचार की कलई खोल दी. पीड़ितों का आरोप है कि नौकरी पर रखने के नाम पर कंपनियों ने तीन–तीन लाख रुपये वसूले. कार्यालय में लगने वाले उपकरण भी कर्मचारियों से ही खरीदवाए और एक झटके में ही नौकरी से बाहर भी कर दिया, पैसे भी वापस नहीं किए. उल्टा नौकरी के दौरान जो 11,506 रुपये सैलरी दे रहे थे, वह भी महीने में कंपनियों के प्रतिनिधि वापस ले रहे थे.

मुख्यमंत्री योगी ने दिया जांच का आदेशः नौकरी से निकल गए पीड़ित जब कंपनियों के भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर परिवहन विभाग पहुंचते हैं तो यहां उन्हें टाल दिया जाता है. सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारियों के पास भेज देते हैं और जूनियर अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाकर पीड़ितों को वापस घर भेज देते हैं. यह सिलसिला पिछले कई माह से चल रहा है. जब पीड़ितों को महसूस हुआ कि अब उनकी सुनवाई परिवहन विभाग में नहीं होगी तो वह सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचे. यहां पर पीड़ितों ने अपनी

आपबीती मुख्यमंत्री को सुनाई जिसके बाद सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और दोषी कंपनियों पर कार्रवाई हो तथा पीड़ितों को न्याय दिया जाए.

जांच शुरू होने से जगी आसः इसके बाद विभाग में खलबली मच गई, आनन–फानन में वही अधिकारी जो पीड़ितों से मिलने तक से कतरा रहे थे, वही वापस फोन कर दफ्तर में मिलने के लिए बुलाने लगे. अब पीड़ितों की सुनवाई शुरू हुई है और मामले की जांच भी गंभीरता से शुरू करने की बात कही गई है. नौकरी से निकाले गए पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया. रायबरेली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद से हटाए गए पीड़ित अखिलेश का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए लगातार परिवहन विभाग के अधिकारियों के कई माह से चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. झूठी दिलासा अधिकारी देते रहे. थक हारकर जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे तो वहां पर अब आस जागी है कि न्याय मिलेगा.

लाखों की घूस और उपकरण खरीद के बिलः भ्रष्टाचार फैला रही कंपनियां ब्लैकलिस्ट होंगी और हमें हमारी नौकरी वापस मिलेगी. रायबरेली में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी करने वाले अनुज को बिना बताए ही नौकरी से हटा दिया गया. पीड़ित अनुज ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा सुनाई तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें भरोसा दिया कि जो भी कंपनियां गलत कर रही हैं, उनकी जांच कराई जाएगी और न्याय मिलेगा. अनुज का कहना है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हमें उम्मीद है कि अब हम लोगों को नौकरी वापस मिलेगी और कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी. उनका कहना है कि कंपनियां मानकों का उल्लंघन कर रही हैं, तय संख्या से ज्यादा भर्तियां की गईं, जिससे कमाई की जा सके. सभी से तीन लाख से लेकर पांच लाख रुपये लिए गए हैं, अभी रोजमार्टा कंपनी ने 15 नई भर्ती की हैं. यह सब कंपनियां बहुत गलत कर रही हैं, अब जांच में सब सामने आ जाएगा.

परिवहन मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासनः पीड़ित नीरज यादव का कहना है कि मुझे कंपनी ने कानपुर में नौकरी पर रखा था. ढाई लाख रुपये भर्ती के नाम पर लिए गए और वहां पर कंप्यूटर से लेकर सीपीयू और अन्य उपकरण खरीद कर लगाने के लिए कहा गया जिसका मेरे पास बिल भी है. सारे बिल और दस्तावेज जनता दरबार में मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं. इन कंपनियों ने परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैलाया है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है तो अब गंभीरता से जांच होगी तो हमें जरूर न्याय मिलेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह से जब सवाल किया गया कि आखिर कंपनियों ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया तो फिर गंभीरता से जांच क्यों नहीं की जा रही है? इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी. अगर कंपनियां जिम्मेदार होंगी तो ब्लैकलिस्ट करेंगे और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जाएगा.

केजरीवाल ने पूछा था नितिन नवीन कौन हैं? पीएम मोदी ने बिना नाम लिए दिया जवाब

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पूछा कि नितिन नवीन कौन हैं? इसके बाद से बीजेपी के सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नितिन नवीन से पूछा आप कौन हैं, उसके बाद से ही इसपर चर्चा शुरू हो गई।

इसके बाद एक पत्रकार पीयूष पद्माकर जिन्होंने नितिन नवीन के साथ पढ़ाई की है, उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें बताई। पत्रकार के ही पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'यह सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है।' पत्रकार पीयूष पद्माकर ने नितिन नवीन को अपना दोस्त बताते हुए पुराना किस्सा शेयर किया।

पीयूष ने अपने पोस्ट में लिखा, 'नितिन नवीन कौन? नितिन कैसे यहां तक पहुंचे? क्या नितिन की तरह कोई और भी 45 साल में बीजेपी अध्यक्ष बन सकता है? नितिन ने आज लखनऊ में अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में कुछ बातें बीजेपी नेताओं को बताई। नितिन ने जो बातें नहीं बताई वो बताता हूं। ये कहानी साल 1998 से शुरू होती है। मैं और नितिन दोनों

दिल्ली में ही पढ़ते थे। दोनों ने बारहवीं की पढ़ाई पूरी की। वो उरङ्कट में पढ़ता था और मैं केंद्रीय विद्यालय में। नितिन के पिताजी विधायक थे लेकिन मुझे बहुत मानते थे। मेरे पिताजी और नवीन जी बरसों पुराने दोस्त थे।'

पीयूष ने बताया कि 1998 के मई और जून के महीने में मैं और नितिन साथ एक ही कमरे में रहते थे। उन्होंने बताया, '12वीं पास होने के बाद हम दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में दाखिले की दौड़ में शामिल हुए थे। नितिन विधायक का बेटा था लेकिन घमंड एक पैसे का नहीं। लंच में बीस रुपए की थाली हम शेयर करते थे ताकि दस रुपए बच सके। डीटीसी बस में चलते थे, ताकि ऑटो का किराया बच सके। टैक्सी ले लें, इतनी बात नितिन के मुंह से कभी निकली भी नहीं। उस जमाने में टैक्सी का मतलब पचास रुपये से ऊपर का खर्च था। हमारे छह सात दोस्त अगर आ जाते तो हम दोनों सोचते थे आज थाली कैसे ऑर्डर की जाए ताकि कम खर्च हो। उस वक्त भी नितिन ने कभी किसी को दिखाने या जताने के लिए भी नहीं कहा– वो टछ्रअ का बेटा है।'

पीयूष ने आगे बताया, 'जून के बाद अगले कुछ महीने हम साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। दिल्ली के क्ख ए७३ील्ल२ङ्गल्ल इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हैं। रहने का मन तो वहां था। लेकिन मैं, नितिन, विश्वजीत और सीताराम , चार दोस्त मिलकर भी दिल्ली–92 पटपड़गंज के अपार्टमेंट्स में फ़्लैट नहीं ले पाए। मुझे आज भी याद है वाघवा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी। बेंच पर मैं और नितिन नवीन बैठे थे। सस्ता मकान दिलाने की बात कह रहे थे। उसने पूछा पिताजी क्या करते हैं। मैंने ही नितिन का भी परिचय करवाया। जैसे ही दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को पता चला किरायेदार के पिता बिहार की राजधानी पटना के विधायक हैं उसने महंगे फ़्लैट दिखाने शुरू कर दिए। बाद में नितिन ने ही कहा, हमारा बजट महीने का दो हजार है। पापा इससे ज्यादा नहीं देंगे। रहना, खाना, कॉलेज जाना, सब दो हजार रुपए में करना होगा। इसके बाद अपार्टमेंट में रहना भूलना पड़ा।'

पीयूष के अनुसार, 'पश्चिम विनोद नगर के मंडावली इलाके में अंदर की गली में आज का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने तीन दोस्तों के साथ रहने लगा। नौकर या मेड रखने के पैसे थे नहीं। दो दोस्त सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाते तो बाकी दो दोस्त बर्तन धोते। झाड़ू पोछा लगाते। शुरू शुरू में मैं और नितिन एक साथ ड्यूटी पर लगे। दोनों मिलकर झूठे बर्तन भी धो लेते थे। झाड़ू भी लगा लेते थे। पोछा भी। फिर फटाफट तैयार होकर दो बस बदलकर कॉलेज पहुंच जाते थे। नितिन उस जमाने में भी चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा अनुशासित और मिलनसार था। झगड़े हमारे होते तो सुलझाता नितिन था।'

'आमिर खान को हिंदू औरतें पसंद, अब तक 3 के साथ', भाजपा की 37 साल की मुस्लिम महिला नेता का बड़ा बयान, मचा हंगामा

(जीएनएस)।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ एक निजी समारोह में शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरूआत की है। शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद जहां फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर बहस का दौर भी शुरू हो गया है।

इसी बीच इखढ की महिला नेता नाजिया इलाही खान का एक बयान सामने आया है, जिसने आमिर खान–गौरी स्प्रैट की शादी की चर्चा को और तेज कर दिया है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग–अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

नाजिया इलाही खान के बयान से बढ़ी हलचल

–आमिर खान की तीसरी शादी पर प्रतिक्रिया देते हुए नाजिया इलाही खान ने एक्टर की पिछली शादियों का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आमिर खान की सभी पत्नियां हिंदू

समुदाय से क्यों रही हैं। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि एक्टर ने जिन महिलाओं से शादी की है, वो सभी हिंदू थीं और बाद में उनसे तलाक हो गया।

–नाजिया इलाही खान ने आगे ये भी सवाल किया कि अगर आमिर खान को हिंदू महिलाओं से शादी करना पसंद है, तो क्या उन्हें धर्म परिवर्तन पर भी विचार करना चाहिए।

उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस का माहौल बन गया है। हालांकि आपको बता दें कि आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट ईसाई धर्म का पलान करती हैं।

–गौरी स्प्रैट एंग्लो–इंडियन मूल की हैं। वह मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं। फिलहाल वह आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा वह हेयरड्रेसिंग और सैलून बिजनेस से भी जुड़ी हुई हैं। –गौरी स्प्रैट के पिता तमिल–ब्रिटिश और मां पंजाबी–आयरिश मूल की थीं। उनके दादा ब्रिटिश थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था।

–मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट ईसाई धर्म का पालन करती हैं। उनके पिता तमिल–ब्रिटिश और मां पंजाबी–आयरिश थे। ऐसे में उनके घर पर कई तरह के त्योहार मनाए जाते थे। गौरी खुद को गर्व से भारतीय मानती हैं और ईसाई धर्म का ही पालन करती हैं। आपको बता दें कि गौरी स्प्रैट एक 6 साल के बेटे की मां भी हैं।

सलमान खान की हीरोइन के पास 2000 करोड़ की संपत्ति, करियर के पीक पर छोड़ी इंडस्ट्री, फिर कैसे हो रही इतनी कमाई

(जीएनएस)।

एक समय ऐसा था जब साउथ सिनेमा और बॉलीवुड में एक्ट्रेस रंभा का नाम सफलता की गारंटी माना जाता था। अपनी खूबसूरती, शानदार डांस और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी। महज 17 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली रंभा ने बहुत कम समय में खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया था।

1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरूआती सालों में रंभा की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी। तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में उन्होंने लगातार काम किया और हर भाषा के दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।

फिल्मी करियर के शुरूआती दौर में ही रंभा ने साउथ इंडियन सिनेमा के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। चिरंजीवी, नागार्जुन, बालकृष्ण, वेंकटेश और राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज एक्ट्रों के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में रजनीकांत और विजयकांत जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी कई चर्चित फिल्मों में काम किया। उनकी लोकप्रियता धीरे–धीरे पूरे देश में फैल गई और बॉलीवुड के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए।

–हिंदी सिनेमा में रंभा को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सलमान खान के साथ मिली। दोनों की ऑनस्क्रीन

केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। 'बंधन', 'बेटी नंबर 1' और 'घरवाली बाहरवाली' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में भी मजबूत पहचान दिलाई।

–उस दौर में रंभा उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल थीं, जो एक साथ कई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थीं और हर जगह सफलता हासिल कर रही थीं। यही वजह थी कि उन्हें उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में भी गिना जाता था।

जब बदलने लगा करियर का दौर

–लंबे समय तक सफलता का स्वाद चखने के बाद रंभा के करियर में बदलाव आने लगा। नई एक्ट्रेसेस की एंट्री के बीच उन्हें पहले जैसे लीड किरदार मिलने कम हो गए। धीरे–धीरे उनके पास छोटे और सीमित रोल आने लगे।

–एक इंटरव्यू में रंभा ने बताया था कि उन्हें कुछ ऐसे किरदार ऑफर किए जा रहे थे, जिनसे वह सहज महसूस नहीं करती थीं। उनके मुताबिक कई फिल्मों में उन्हें ऐसे रोल करने के लिए कहा गया जो उनकी छवि और पसंद के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को ठुकराना बेहतर समझा और केवल नाम के लिए काम करने से इनकार कर दिया।

जब अधिकतर लोग मान रहे थे कि रंभा अभी कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेंगी, तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। साल 2010 में उन्होंने कनाडा के बिजनेसमैन इंद्रकुमार पद्मनाथन से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ कनाडा में बस गईं। ये फैसला उस समय आया जब वह अभी भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थीं।

शादी के बाद रंभा ने खुद को सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा और अपने पति के कारोबार में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कई व्यावसायिक परियोजनाओं के प्रबंधन और संचालन में भी शामिल हैं। फिल्मी करियर से अलग ये उनकी जिंदगी का नया अध्याय था, जहां उन्होंने एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में पहचान बनाने की कोशिश की।

आज रंभा तीन बच्चों की मां हैं। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। वह अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रही हैं और पारिवारिक जीवन का मजा उठा रही हैं।

सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने बच्चों और परिवार की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। फैंस भी उनकी पोस्ट्स पर जमकर प्यार लुटाते हैं और उनकी निजी जिंदगी की झलकियां देखना पसंद करते हैं।

नीति टेलर 'थप्पड़ मारा, सिगरेट से सुलगाया', कौन है नीति टेलर? रोते हुए बोलीं–प्यार के बदले मिला घाव

(जीएनएस)।

टीवी की चुलबुली अभिनेत्रियों में से एक नीति टेलर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है, वजह है उनका वो दर्दभरा खुलासा, जिसे सुनने के बाद उनके फैंस बुरी तरह आहत और दुखी हैं। दरअसल प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो 'अलायंस' में नीति ने अपनी रीयल लाइफ का दर्द शेयर किया।

उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा कि 'वो भी एक समय में टॉक्सिक रिलेशनशिप में थीं, जिसने उन्हें इतना दर्द दिया है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकती हैं।' नीति ने शो पर मिनी माथुर, रूही दोसानी और देल्बार आर्या के साथ बातचीत के दौरान यह बात बताई।

अपनी ज़िंदगी के उस दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 'अक्सर बाली उम्र में आपे से गलतियां हो जाती हैं, आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं, मैं 15 साल की थी, मुझसे भी ऐसी गलती हुई, मैं एक हिंसक और साइकोटिक इंसान के चंगुल में फंस गई थी।'

'एक रात उसका दिमाग फिर गया, उस दिन उसका जन्मदिन था। पहले वो किसी बात पर काफी नाराज हो गया और उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर सिगरेट से जला दिया। मैं दर्द से बुरी तरह से कांप उठी थी, उस जलन के घाव का निशान आज भी मेरी जांघ पर है।'

मुझे प्यार के बदला घाव मिला: नीति टेलर

'लेकिन मैंने उसी वक्त इस रिलेशन को खत्म करने का फैसला किया और उससे बस इतना कहा, 'अलविदा, फिर मिलेंगे' लेकिन खैर, उस समय मैं बहुत छोटी थी। जब आप नासमझ होते हैं, तो लोगों के चरित्र को ठीक से नहीं समझ पाते। वह सनकी था और इसलिए मुझे प्यार के बदला घाव मिला।'

13 अगस्त 2020 को हुई थी नीति और परीक्षित बावा की शादी

इसके बाद उन्होंने अपनी मैरिजड लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा कि 'लोग बिना समझे कुछ भी उड़ा देते हैं। दरअसल नीति ने परीक्षित बावा के साथ 13 अगस्त 2020 को शादी की थी, दोनों का ये प्रेम विवाह है और दोनों साथ में काफी खुश भी हैं लेकिन साल 2024 में उनके अलग होने की अफवाहें उड़ीं थीं, जिस पर इस कपल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। नीति ने कहा कि उस वक्त हमें और हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था लेकिन हम चुप थे क्योंकि हर बकवास बातों पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है।

कौन हैं नीति टेलर?

आपको बता दें कि 8 नवंबर 1994 को दिल्ली में जन्मी नीति टेलर के पिता गुजराती और मां बंगाली ईसाई हैं। वो टीवी की चुलबुली अभिनेत्रियों में से एक हैं। 15 साल की उम्र में, टेलर ने 2009 में 'प्यार का बंधन' से टेलीविजन पर डेब्यू किया।उन्हें असली पहचान टळश इंडिया के शो 'कैसी ये यारियां' में पार्थ समथान के साथ नंदिनी मूर्ति का किरदार निभाकर मिली।

2016 में वह सिद्धार्थ गुप्ता के साथ म्यूज़िक वीडियो "परिंदे का पागलपन" में नजर आई थी, उन्होंने क्राइम थ्रिलर 'गुलाम' में परम सिंह के साथ शिवानी का किरदार निभाया था और 2019 में, टेलर ने 'इश्कबाज' में मन्नत कौर खुराना से लोकप्रियता हासिल की थी। साल 2022 में, उन्होंने 'झलक दिखला जा 10' में हिस्सा लिया और कोरियोग्राफर आकाश थापा के साथ उनकी जोड़ी बनी। 2023 में, टेलर सोनी टीवी के शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में रणदीप राय के साथ प्राची कपूर का किरदार निभाती हुई नजर आई थी,इन दिनों प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो 'अलायंस' का हिस्सा है।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी मंजूरी, सभी जनपदों में लागू होगी मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 29 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज रवाना हो गये। इस बैठक में शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रीगण सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, सुनील शर्मा, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव और योगेंद्र उपाध्याय ने पास प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

'स्टार्टअप मिशन' की स्थापना को मंजूरी

आई टी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 'स्टार्टअप मिशन' की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना

पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। लघु एवं सीमांत कृषकों, पशुपालकों और डेयरी फार्म पशुपालकों जिन पशुओं को पाले जा रहे हैं, उनके सुरक्षित एवं किसी महामारी, पशु अपंग या मृत्यु होने पर पशुओं का बीमा कराने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। यह समस्त 75 जनपदों में लागू किया जाएगा। इसमें 85 प्रतिशत राज्यांश और 15 प्रतिशत लाभार्थी का अंश होगा।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में सौ-सौ बेड के अस्पताल के निर्माण का निर्माण होगा। इसके साथ वाराणसी में श्रम विभाग के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए निःशुल्क जमीन आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। गोरखपुर और मुरादाबाद में अस्पताल के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज(उच्चीकृत) निर्माण के लिए 13 एकड़ भूमि भारत सरकार को आवंटित की जाएगी। वाराणसी मेडिकल कॉलेज(उच्चीकृत) में 50% एमबीबीएस सीट श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18 प्रतिशत राज्य सरकार का आवंटन होगा और सात प्रतिशत केंद्र सरकार छात्रों का चयन करेगी।

सीधी भर्ती के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन

खेल- युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से (लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर करके) चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। क्रीड़ाधिकारी के नौ पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के तीन पद और उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की एसओपी को हरी झंडी

उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र की तीन संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए एलओपी जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें स्वामी ब्रह्मानन्द चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली महर्षि महेश योगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसायटी गाजियाबाद के गाजियाबाद में यूनिवर्सिटी की स्थापना और एंग्लो संस्कृत कॉलेज फतेहपुर के फतेहपुर में यूनिवर्सिटी स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

राज्यकार्मिको को वर्दी धुलाई व वर्दी के पैसे के प्रस्ताव को स्वीकृति

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका परिषद जलालाबाद का नाम परिवर्तित करके "परशुरामपुरी" करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार से एनओसी प्राप्त होने के बाद मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।

वेतन समिति 2016 द्वारा राज्यकार्मिको को वर्दी धुलाई व वर्दी के पैसे के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गोरखपुर नगर निगम व मुरादाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बांड निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गोरखपुर का 80 करोड़ और मुरादाबाद का 50 करोड़ का बांड जारी होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए प्रस्ताव स्वीकृत। इनको पांच लाख की कैशलेस चिकित्सा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय

कृषि विभाग के मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि रायबरेली में चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के माध्यम से उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रायबरेली के तहसील सदर में ग्राम पडेरा में कृषि विभाग की 20 हेक्टेयर भूमि निशुल्क प्रदान की जाएगी। यहां उद्यान महाविद्यालय व रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।

संगठन-सरकार में तालमेल, गुटबाजी पर लगाम... सीएम के साथ डिप्टी सीएम का अलाइन कर बड़ा सियासी संदेश दे गए नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ प्रवास के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं की एकजुटता का संदेश दिया. उन्होंने नेताओं को यह संदेश दे दिया कि पार्टी की लाइन पर ही चलना होगा.

(जीएनएस)।

लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिन के प्रवास पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे. अपने इस प्रवास के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में नितिन नवीन ने साफ कर दिया कि बड़े नेताओं के बीच मतभेद या मनभेद के लिए कोई जगह नहीं है. पिछले पांच साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब शाम के नाश्ते पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.

पहली बार केशव मौर्य के घर शाम के नाश्ते पर नितिन नवीन और सीएम योगी भी मौजूद थे. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी केशव मौर्य के घर मौजूद रहे. इस मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच की दूरी कम होती दिखाई दी और यही बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे का मुख्य मकसद भी था कि मतभेदों को दूर कर एकजुटता का संदेश दिया जाए.

बीजेपी की समन्वय बैठक में भी नितिन नवीन ने दो टूक कहा कि आपसी मतभेदों के लिए कोई जगह नहीं है. संगठन और सरकार को एक पेज पर आना होगा. केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर अब कोई संशय नहीं है. साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी नेताओं को पार्टी की तय लाइन पर ही चलना होगा.

नितिन नवीन ने यह भी साफ कर दिया कि कोई खुद को पार्टी से बड़ा न समझे, ना ही कोई यह सोचे कि पार्टी और सरकार में रहते हुए माहौल खराब कर अपनी बात मनवा लेंगे. कार्यकताओं की सुध सरकार और पार्टी को लेनी होगी. बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उपमुख्यमंत्रियों और और सभी पूर्व अध्यक्षों को भी एक लाइन में अलाइन किया.

दो दिन में नितिन नवीन ने लखनऊ में कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया कि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम साथ-साथ खाना और नाश्ता करते,आम खाते, डिनर करते नजर आए. बीजेपी के इन बड़े नेताओं की इस तरह की मुलाकातें पहले कभी नहीं दिखी थीं. नितिन नवीन ने पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्षों को एक साथ बुलाकर बैठक ली, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, स्वतंत्रदेव सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सूर्य प्रताप शाही सहित कई पुराने अध्यक्ष शामिल हुए.

इस मीटिंग का संदेश भी साफ था कि सभी का अनुभव 2027 के लिए चाहिए, लेकिन यहां भी नितिन नवीन ने वही बात दोहराई- माहौल खराब न हो इसकी जिम्मेदारी भी पुराने अध्यक्षों पर है. प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक में नितीन नवीन ने साफ कर दिया 2027 के चुनाव में जमीनी स्तर पर सभी को जुटना होगा. कार्यकताओं की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और पार्टी की है. नितिन नवीन ने अपनी दो दिनों की इस यात्रा में यह तो साफ कर दिया कि पार्टी में कोई भी गुटबाजी स्वीकार नहीं होगी और सभी को एक लक्ष्य के लिए एक साथ चलना होगा.

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कटेगा बस 15 रुपया टोल, करना होगा ये जुगाड़, जल्द होने वाला है शुरू

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे. यह एक्सप्रेसवे महज 63 किलोमीटर का है. बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर बहुत ही कम टोल लगेगा.

(जीएनएस)।

उन्नावः उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण रॉकेट की स्पीड से हो रहा है. बीते कुछ महीनों में लगातार नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुए हैं, जिसपर अब लोग सफर तय कर रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक और नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 13 जुलाई को होगा. यह एक्सप्रेसवे कानपुर से लखनऊ जाएगा, जिसकी दूरी महरज 63 किलोमीटर है. यह यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है. अब बात करें इसके टोल की तो बता दें कि महज 15 रुपये टोल कटेगा. दरअसल, अगर आपकी गाड़ी का 3075 रुपये वाला एनुअल फास्टैग पास है तो हर ट्रिप का खर्च करीब 15 रुपये आएगा.

जानें कार, जीप और बस के लिए कितना देना होगा टोल

अगर आपके पास ये वाला फास्टैग नहीं है और नॉर्मल रिचार्ज करा रखा है आपने तो कार, जीप और वैन से एक तरफ का सफर करने पर 275 रुपये देने होंगे. लेकिन अगर 24 घंटे के भीतर वापसी कर लेते हैं तो महज 415 रुपये देने होंगे. वहीं हल्के कॉमर्शियल वाहन, बस, ट्रक और मल्टी एक्सल वाहनों के लिए भी अलग-अलग रेट हैं. जैसे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 445 रुपये बस और ट्रक के लिए 935 रुपये, जबकि मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 1020 रुपये तय की गई है.

सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ 13 जुलाई को देश और प्रदेश वासियों को सौगात देंगे. बता दें कि उन्नाव के आजाद मार्ग से कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू होता है. बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से जो कानपुर से लखनऊ जाने में ढाई से तीन घंटे लगते थे. वहीं अब 60 मिनट लगेंगे. यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है. इस एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने और त्वरित सहायता के लिए इस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और दो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

लखनऊ अग्निकांड का असर, मेरठ में कोचिंग संस्थानों पर मेडा की कार्रवाई, 15 मिनट में आधा दर्जन केंद्र सील

(जीएनएस)।

मेरठ, लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने बच्चा पार्क स्थित स्टार प्लाजा के करीब आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद संचालन जारी था।

लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर के कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को एमडीए की टीम पुलिस बल के साथ बच्चा पार्क चौराहा स्थित स्टार प्लाजा पहुंची और करीब 15 मिनट के भीतर आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस बल के साथ पहुंची टीम, तेजी से हुई सीलिंग

एमडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ स्टार प्लाजा पहुंची और पहले से चिन्हित कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। महज 15 मिनट के भीतर करीब आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों को सील कर टीम वहां से रवाना हो गई। कार्रवाई के दौरान परिसर में मौजूद विद्यार्थियों और संचालकों में हड़कंप मचा रहा।

संचालकों का आरोप, सामान निकालने का भी नहीं मिला समय

कोचिंग संचालकों का कहना है कि कार्रवाई इतनी तेजी से की गई कि उन्हें संस्थानों के भीतर रखा सामान तक बाहर निकालने का अवसर नहीं दिया गया। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

एमडीए का दावा, पहले ही दिए जा चुके थे नोटिस

एमडीए अधिकारियों का कहना है कि संबंधित कोचिंग संस्थानों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद संस्थानों का संचालन जारी मिला। इसी आधार पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

7 साल के बच्चे ने रात 1 बजे क्यों बुक की रैपिडो? जब राइडर को बताई वजह तो बोला- पापा को जगाओ, उनके साथ जाओ

(जीएनएस)।

लखनऊ के रैपिडो राइडर और इंटरनेट पर वीडियो क्रिएटर रोहित वर्मा को रात 1 बजे एक रैपिडो की राइड मिलती है। लेकिन कस्टमर की उम्र सिर्फ 7 साल की होती है और

उसे चाय पीने जाना होता है। जिसके चलते रोहित मना कर देते हैं। इसके बाद बच्चा उनपर भड़क जाता है और दोनों की कहासुनी की वीडियो अब वायरल है।

यह थोड़ा अटपटा लग सकता है कि रात के 1 बजे कोई छोटा बच्चा रैपिडो की राइड बुक करें, वो भी सिर्फ इसलिए की उसे चाय पीनी है! मगर लखनऊ में रोहित नाम के रैपिडो राइडर के साथ कथितौर पर ऐसा ही कुछ हुआ है। इंटरनेट इस वायरल वीडियो को 'मजेदार' ढंग से ले रहा है और बच्चे और रैपिडो वाले के बीच हुई बातचीत पर जमकर रिएक्शन दे रहा है।

रैपिडो वाला लोकेशन पर पहुंचकर बच्चे को फोन करता है और बोलता है कि 'सर, मैं लोकेशन पर खड़ा हूं और आप मुझे नहीं दिख रहे।' इस पर बच्चा बोलता है कि 'दो कुत्ते खड़े है, भौंक रहे हैं।' इस पर रैपिडो वाला कहता है कि उसे आसपास कुत्ते नहीं दिख रहे हैं। वह बच्चे से कोई लैंडमार्क लोकेशन पूछता है। इस पर बच्चा बोलता है कि 'मैं कुछ नहीं जानता, मुझे लेने आओ।

बच्चा बात करते हुए जब रैपिडो राइडर को अपनी उम्र 7 साल बताता है, तो वह चौंक जाता है। रोहित उससे पूछते हैं कि 'इतनी रात को रैपिडो क्यों बुक की है आपने?' तो बच्चा बोलता है कि 'उसे चाय पीने जाना है।' इस पर रैपिडो वाले का कहना होता है कि रात के 1 बज रहे हैं और आपको चाय की पीयास लगी है। आपके पापा कहा है? इस पर बच्चा उसे दोबारा जल्दी आने को कहता है। मगर राइडर उसे अपने पापा के साथ जाने को कहता है।

बच्चा बताता है कि पापा सो रहे हैं, तो रैपिडो वाला कहता है कि पहले उन्हें जगाइए मैं ऐसे नहीं आउंगा। इसके जवाब में बच्चा भी खिसियाकर कहता है 'ठीक है मत आइए।' रैपिडो वाला फोन काटते हुए उसे 'बेवकूफ बच्चा' भी बोलता है। इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है।

स्टाग्राम पर रोहित वर्मा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि 'बच्चे को रात 1 बजे लगी चाय पीने की तलब।' 22 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 64 लाख से अधिक लोगों ने देखने के साथ ही ढाई लाख से अधिक बार लाइक भी किया है। जबकि पोस्ट पर 3800 के पार कमेंट्स आए है।

रैपिडो राइडर और बच्चे की इस बातचीत ने कमेंट सेक्शन का माहौल और भी मजेदार बना दिया। लोग इस पूरी बातचीत और कहासुनी में अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट्स में बता रहे हैं। जबकि कुछ लोग आज कल के बच्चों के दिमाग को भी व्यंगात्मक रूप से सलाम कर रहे हैं। एक यूजर का कहना था कि 'चाय जरूरी है, आपको बच्चे को ले जाना चाहिए।'

पाकिस्तान एचआईवी आउटब्रेकः इलाज कराने गए, एचआईवी लेकर लौटे! पाकिस्तान में 78 बच्चों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के कराची शहर से एक बेहद दर्दनाक, शर्मनाक और डराने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए कई मासूम बच्चे एचआईवी (HIV) से संक्रमित पाए गए हैं। सिंध प्रांत के मंत्री सईद गनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि रक्ख्ए इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कुलसुम बाई वलीका अस्पताल में अब तक कम से कम 78 बच्चों में लक्ष्य संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी गई है।

कौन सा अस्पताल है विवाद के केंद्र में?

यह मामला कुलसुम बाई वलीका अस्पताल का है, जिसे सिंध कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संस्थान (SESSI) के तहत श्रम विभाग चलाता है। इतने बड़े स्तर पर बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने प्रांत की सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

कब सामने आया मामला और क्या हुई कार्रवाई?

सिंध के श्रम मंत्री सईद गनी ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2025 में विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके लगभग एक महीने बाद यानी अक्टूबर 2025 के आखिर में अस्पताल में बच्चों के लक्ष्य संक्रमित होने का मामला सामने आया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 29 अक्टूबर 2025 को पहली जांच समिति बनाई। इस समिति की शुरूआती रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के कई डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 7 नवंबर 2025 को प्रांतीय लोकपाल के आदेश पर दूसरी स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की गई ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

सरकार ने क्या कहा?

सईद गनी ने कहा कि केवल कर्मचारियों को निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि जांच में डॉक्टरों, नर्सों या अन्य मेडिकल स्टाफ की लापरवाही साबित होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और किसी भी दोषी को उसके प्रभाव या पद के कारण बचाया नहीं जाएगा।

संक्रमित बच्चों की संख्या को लेकर विवाद

इस मामले में संक्रमित बच्चों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील तारिक मंसूर का दावा है कि अस्पताल की लापरवाही से करीब 200 बच्चे लक्ष्य की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने अदालत में इस संबंध में कई दस्तावेज और सबूत भी पेश किए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि फिलहाल केवल 78 बच्चों की पुष्टि हुई है। मंत्री के मुताबिक, कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से जांच में सामने नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से संक्रमित बच्चों की वास्तविक संख्या का पता लगाने में मुश्किल हो रही है।

अदालत में क्या मांग की गई?

याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बनाया जाए। साथ ही सभी प्रभावित बच्चों को जीवनभर मुफ्त और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उनके परिवारों को उचित आर्थिक सहायता और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

संक्रमण कैसे फैला? जांच जारी

स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि अस्पताल में एक ही सिरिंज का बार-बार इस्तेमाल किया गया, जिससे संक्रमण फैला। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। सईद गनी का कहना है कि अस्पताल में ऑटो-डिसेबल सिरिंज इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें दोबारा उपयोग करना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं हुई, तो संक्रमित खून चढ़ाने, सर्जिकल उपकरणों की सफाई में लापरवाही या अस्पताल की संक्रमण नियंत्रण प्रणाली जैसी दूसरी संभावनाओं की भी गंभीर जांच की जानी चाहिए।

पीड़ित बच्चों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

इस घटना के बाद प्रभावित परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह सिर्फ जांच तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के भविष्य की भी जिम्मेदारी उठाए।

सईद गनी ने कहा कि सरकार केवल मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानेगी। सभी प्रभावित बच्चों को पूरी तरह मुफ्त और लगातार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परिवारों को जरूरी आर्थिक सहायता देने और बच्चों को सामाजिक भेदभाव से बचाने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। अब सभी की नजर सिंध हाई कोर्ट की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस गंभीर स्वास्थ्य संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी।